

## नागरिक विविध

न्यायमूर्ति आर.एस. नरूला और राजेंद्र नाथ मित्तल के समक्ष

मांगे राम आदि, याचिकाकर्ताओं;

*बनाम*

हरियाणा राज्य आदि, उत्तरदाताओं।

1972 की सिविल रिट संख्या 259

4 मई, 1972

*हरियाणा प्रथम संशोधन अधिनियम (1971 का XIX) द्वारा संशोधित पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का IV) - धारा 3 (1), 5 (2), 6 (1), 13 A, 13B - हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम (1971) - नियम 38 (2) और (3), 39 (3) - हरियाणा ग्राम पंचायत (महिला पंचों का सह-विकल्प) नियम (1971) - नियम 3 (2), 3 (3) और 4 (3) 6(1), संशोधन से पहले पंचायत अधिनियम - इसके तहत एक महिला पंच का सह-विकल्प - क्या "निर्वाचन", चुनाव याचिका में चुनौती दिए जाने में सक्षम है - संशोधन के बाद ऐसा सह-विकल्प - चाहे "चुनाव" के बराबर हो - चुनाव नियमों के नियम 38 (2) और (3) के तहत आवश्यक सात दिनों की अवधि, सह-विकल्प नियमों के नियम 3 (2) और (3) और नियम 30 (3) के तहत आवश्यक तीन दिनों की अवधि/चुनाव नियमों और सह-विकल्प नियमों की धारा 4 (3) - चाहे नोटिस "भेजने" या "देने" से शुरू होती है - अभिव्यक्ति "तीन दिन की स्पष्ट सूचना" - क्या "तीन स्पष्ट दिनों के नोटिस" का पर्याय है - सरपंच के चुनाव के लिए बैठक - नियम 38 (2) और (3) और नियम 39 (3) की आवश्यकताएं, पंचों को नोटिस जारी करने के लिए निर्वाचन नियम - चाहे ऐसे नोटिस जारी होने के बाद निर्वाचित या सहयोजित पंच पर लागू हों - भारत का संविधान - अनुच्छेद 226 - चुनाव याचिका दायर किए बिना चुनाव की वैधता पर सवाल उठाना - अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का असाधारण संवैधानिक अधिकार क्षेत्र - क्या लागू किया जा सकता है।*

### *अभिनिर्धारित*

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 6 (1) के तहत, जैसा कि हरियाणा प्रथम संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा इसके संशोधन से पहले था, और हरियाणा ग्राम पंचायत (महिला पंचों का सह-विकल्प) नियम, 1971 के निर्माण से पहले, महिला पंच का सह-विकल्प एक चुनाव नहीं था और इसलिए इसे चुनाव याचिका द्वारा प्रश्न में नहीं बुलाया जा सकता था।

### *अभिनिर्धारित*

संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा यथासंशोधित अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परंतुक के तहत महिला पंच के सह-विकल्प को अधिनियम की धारा 13-ए (ई) के अर्थ के भीतर "चुनाव" बनाया जाता है और जहां तक सह-चयनित महिला पंच अधिनियम की धारा 3 (1) के अर्थ के भीतर एक "पंच" है। हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम, 1971 के नियम 44 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 13-बी के तहत उनके निर्वाचन पर सवाल उठाया जा सकता है।

### *अभिनिर्धारित*

हरियाणा ग्राम पंचायत (महिला पंचों का सह-विकल्प) नियम, 1971 के नियम 3 के उप-नियम (3) और संशोधित हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम, 1971 के नियम 38 के उप-नियम (3) में "भेजे गए" शब्द के उपयोग में "भेजा गया" शब्द का बहुत महत्व है। इसी तरह, संशोधित चुनाव नियमों के नियम 39 के उप-नियम (3) के पहले भाग में "सेवा" शब्द का हटना और सह-विकल्प नियमों के नियम 3 के उप-नियम (3) के शुरुआती भाग में उसी शब्द का मिससोन ऐसे उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य वाक्यांशविज्ञान से जानबूझकर अलग होना दर्शाता है। नोटिस के संबंध में दोनों नियमों के संबंधित भाग के उप-नियम (3) में "सेवा" शब्द के बजाय "देना" शब्द का उपयोग किया गया है। एक तीसरा कारक जो इस संबंध में महत्वपूर्ण है, वह यह है कि "सेव्ड" शब्द का उपयोग नियम 38 के उप-नियम (3) के साथ-साथ नियम 3 (चुनाव नियम और सह-विकल्प नियम) के उप-नियम (3) में ब्लॉक के किसी अधिकारी के माध्यम से या

ग्राम सचिव के माध्यम से दिए जाने वाले नोटिस के संबंध में किया गया है। लेकिन डाक द्वारा नोटिस भेजे जाने और बैठक की तारीख के बीच समाप्त होने वाले दिनों की संख्या के विपरीत इस तरह के नोटिस की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए चुनाव नियमों के नियम 38 के उप-नियम (2) और (3) और सह-विकल्प नियमों के उप-नियम (2) और (3) के तहत पंचों को दिए जाने वाले नोटिस की सात दिनों की अवधि और चुनाव नियमों के नियम 39 (3) और सह-विकल्प नियमों के 4 (3) के तहत नोटिस के लिए आवश्यक तीन दिनों की अवधि भेजने या देने की तारीख से शुरू होती है। यानी, नोटिस भेजना न कि संबंधित पंच को नोटिस की डिलीवरी या सेवा के समय से।

#### *अभिनिर्धारित*

चुनाव नियमों और सह-विकल्प नियमों की योजना को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित नियमों में 'तीन दिन की स्पष्ट सूचना' वाक्यांश का उपयोग उसी आवश्यकता को व्यक्त करने के लिए किया गया है जो 'तीन स्पष्ट दिनों के नोटिस' शब्द द्वारा व्यक्त की गई है, जिसका अर्थ है कि 'नोटिस भेजे जाने की तारीख और बैठक आयोजित करने की तारीख के बीच तीन दिन का समय समाप्त होना चाहिए।

#### *अभिनिर्धारित*

निर्वाचन नियमावली के नियम 38 के उप-नियम (3) और उप-नियम (3) के दायरे और नियम 39 के उप-नियम (3) की अपेक्षाएं उस नोटिस पर लागू नहीं होती हैं जो सरपंच के चुनाव के लिए बैठक के नोटिस जारी होने के बाद निर्वाचित या सहयोजित पंच को दिया जाना है। ऐसे पंच को बैठक के पीठासीन अधिकारी द्वारा वैध रूप से नोटिस ऐसे तरीके से दिया जा सकता है जो वह निर्वाचन नियमों के नियम 38 (3) के परंतुक के तहत उचित समझे।

#### *अभिनिर्धारित*

यद्यपि उच्च न्यायालय आमतौर पर चुनाव की वैधता पर सवाल उठाने के लिए एक रिट याचिका पर विचार नहीं करेगा, जिसे अधिनियम के तहत चुनाव याचिका द्वारा प्रश्न में बुलाया जा सकता है, संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उच्च न्यायालय को एक

उपयुक्त मामले में अपने रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से रोकता है जहां राहत देने से इनकार करने से स्पष्ट अन्याय होने की संभावना है और कानून या अधिकार क्षेत्र की त्रुटि स्पष्ट है। चुनाव कार्यवाही के स्वीकृत रिकॉर्ड के चेहरे पर। इस तथ्य के बावजूद कि पंचायत अधिनियम की धारा 13-बी एक चुनाव याचिका को छोड़कर अधिनियम के तहत चुनाव पर सवाल उठाने के सभी उपायों पर रोक लगाती है, यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण संवैधानिक अधिकार क्षेत्र को लागू करने पर रोक नहीं लगाती है।

*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि अधिकार-पृच्छया किसी अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जिसमें उत्तरदाताओं 4 और 5 को क्रमशः पंच और सरपंच के पद धारण करने के उनके अधिकार के बारे में इस माननीय न्यायालय को जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए और उनके सह-विकल्प और चुनाव को रद्द कर दिया जाए।*

याचिकाकर्ताओं की ओर से आर.एस.मित्तल एडवोकेट।

बी.एस. गुप्ता, एडवोकेट-जनरल, हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए 1-3।

एच.एस. हुड्डा, वकील, उत्तरदाताओं 4 से 7 के लिए।

### निर्णय

**न्यायमूर्ति नरूला।** हमें संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस याचिका में पंच के रूप में श्रीमती नन्हटी प्रतिवादी नंबर 4 के सह-विकल्प की वैधता और धन सिंह प्रतिवादी नंबर 5 के ग्राम पंचायत पिचोप्पा कलां, तहसील चरखी दादरी, जिला मोहिंदरगढ़ (हरियाणा) (इसके बाद पंचायत कहा जाता है) के सरपंच के रूप में चुनाव पर फैसला सुनाने के लिए कहा गया है।

मांगे राम याचिकाकर्ता नंबर 1, धन सिंह, चंदर और रामेश्वर, प्रतिवादी नंबर 5 से 7, एक जय चंद, और एक अनुसूचित जाति के एक सदस्य, अर्थात् पहलाद, 5 जुलाई, 1971

को हुए चुनाव में पंचायत के पंच के रूप में चुने गए थे। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा 13 दिसंबर, 1971 को उपरोक्त सभी पंचों को हरियाणा ग्राम पंचायत (महिला पंचों का सह-विकल्प) नियम 4 के तहत पंचायत के लिए एक महिला पंच को सह-चयन करने के लिए 17 दिसंबर, 1971 को सुबह 8 बजे निर्वाचित पंचों की बैठक आयोजित करने के लिए नोटिस (अनुबंध 'ए') जारी किया गया था। 1971 (इसके बाद सह-विकल्प नियमों के रूप में संदर्भित)। उसी दिन प्रतिवादी संख्या 3 ने 17 दिसंबर, 1971 को सुबह 10.30 बजे हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम, 1971 (इसके बाद चुनाव नियम कहा जाता है) के नियम 39 के तहत पंचायत के सरपंच का चुनाव करने के लिए सभी पंचों को एक और नोटिस (अनुलग्नक 'बी') जारी किया। दोनों नोटिस मांगे राम याचिकाकर्ता को 14 दिसंबर, 1971 को मिले थे।

(3) नन्हटी प्रतिवादी नंबर 4 को 17 दिसंबर, 1971 को सुबह 8 बजे आयोजित बैठक में अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार श्रीमती शांति याचिकाकर्ता नंबर 2 को हराकर सह-निर्वाचित महिला पंच के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया था। दूसरी बैठक में, जिसमें नन्हटी ने भी मतदान किया, धन सिंह प्रतिवादी नंबर 5 को मांगे राम याचिकाकर्ता को हराकर सरपंच के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया। 23 दिसंबर, 1971 को मांगे राम और शांति द्वारा यह संयुक्त याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रतिवादी नंबर 4 के सह-विकल्प और सरपंच के रूप में प्रतिवादी नंबर 5 के चुनाव पर सवाल उठाया गया था। याचिका को चुनौती देते हुए प्रतिवादी नंबर 1 (हरियाणा राज्य), प्रतिवादी नंबर 2 (इंस्पेक्टर को-ऑपरेटिव सोसाइटी, चरखी दादरी, जिसने दो बैठकों की अध्यक्षता की) और प्रतिवादी नंबर 5 (निर्वाचित सरपंच) ने अलग-अलग लिखित बयान दायर किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 5 के लिखित बयान के जवाब में प्रतिकृति दायर की है।

(4) इस मामले में शामिल विवाद के गुण-दोष पर पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर ध्यान देने से पहले, इस याचिका की सुनवाई के लगभग अंतिम अंत में प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के लिए श्री एचएस हुड्डा एडवोकेट द्वारा उठाए गए कुछ प्रारंभिक प्रकृति की दो आपत्तियों का निपटान करना आवश्यक है। उन्होंने सबसे पहले तर्क दिया है कि यह याचिका पार्टियों के गलत आचरण से ग्रस्त है क्योंकि पराजित सरपंच और चुनाव के लिए हारे हुए उम्मीदवार को एक महिला पंच के रूप में दो अलग-अलग कार्यालयों के

लिए दो अलग-अलग चुनावों पर सवाल उठाने के लिए रिट याचिका दायर करने में एक साथ शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पहली नजर में यह तर्क काफी आकर्षक प्रतीत होता है। हालांकि, इस मामले के तथ्यों पर, तर्क में अधिकांश आकर्षण इस तथ्य से खो जाता है कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने दोनों चुनावों को उन आधारों पर लागू किया जो दोनों चुनावों में से प्रत्येक के लिए समान हैं। हालांकि श्री मित्तल ने सुझाव दिया कि अगर हमें लगता है कि दो याचिकाकर्ताओं द्वारा एक संयुक्त याचिका दायर नहीं की जा सकती है, तो हम इस मामले की परिस्थितियों में इस याचिका को मांगे राम याचिकाकर्ता नंबर 1 के दावे तक सीमित मानते हुए इस पर विचार कर सकते हैं, सुन सकते हैं और फैसला कर सकते हैं, और उस आधार पर याचिका को खारिज नहीं कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह उनके कहने पर अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम के लिए नहीं कह रहे हैं। विवाद के गुण-दोष पर वकील को सुनने के बाद, हमारी राय है कि भले ही हम याचिकाकर्ता नंबर 1 के दावे पर विचार करें और फैसला करें, हमें सह-चयनित महिला पंच के चुनाव की वैधता के खिलाफ आग्रह किए गए सभी आधारों की वैधता पर फैसला सुनाना होगा, जिससे दूसरा याचिकाकर्ता पीड़ित है। श्री हुड्डा ने अमरीक सिंह वरयाम सिंह बनाम *बी.एस. मलिक और अन्य* ए.आई.आर. 1966 पी.बी. 344 मामले में मेरे फैसले पर अपनी इस आपत्ति के समर्थन में भरोसा किया है। *अमरीक सिंह वरयाम सिंह* के मामले में असली आपत्ति सरपंच और पंच के चुनाव पर सवाल उठाने के लिए दायर की गई एक ही चुनाव याचिका के खिलाफ थी। इन्हीं तथ्यों के आधार पर मैंने कहा था कि अधिनियम की धारा 13-ख और 13-ग तथा निर्वाचन नियमावली के नियम 44 और 45 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र चुनाव याचिका दायर नहीं की जा सकती। हमारे सामने जो मामला है, उसमें हम दो अलग-अलग चुनावों पर सवाल उठाने के लिए एक रिट याचिका दायर करने में दो स्वतंत्र व्यक्तियों के एक साथ शामिल होने की वैधता से चिंतित हैं। हालांकि, हम इस तथ्य को नहीं खो सकते हैं कि न तो संयुक्त याचिका ने किसी भी प्रतिवादी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा किया है, न ही इसने किसी भी तरह से इस मुकदमे बाजी में शामिल मुद्दों को जटिल बनाया है। विद्वान वकील द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम यह सोचने के इच्छुक हैं कि इस मामले के अजीब तथ्यों को देखते हुए और दोनों याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह किए जाने वाले सामान्य आधारों को देखते हुए, यह

नहीं कहा जा सकता है कि यह याचिका याचिकाकर्ताओं की बहुविधता या गलतफहमी के कारण खारिज की जा सकती है।

(5) श्री हुड्डा की दूसरी आपत्ति वास्तव में इस याचिका के लिए जिम्मेदार है जिसे पहली बार में एक खंडपीठ में स्वीकार कर लिया गया है। प्रतिवादी 4 से 7 के वकील के अनुसार, इस याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं ने पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 13-बी के तहत उचित चुनाव याचिकाओं के माध्यम से प्रतिवादी 6 और 7 के पंच के रूप में, प्रतिवादी नंबर 4 के सह-चयनित महिला पंच के रूप में और प्रतिवादी नंबर 5 के सरपंच के रूप में चुनाव पर सवाल उठाने के लिए उनके पास उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का उपयोग नहीं किया है। 1952 (1953 का अधिनियम 4) (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है, जिसे चुनाव नियमों के नियम 44 के साथ पढ़ा जाता है। (प्रतिवादी 6 और 7 को पंच के रूप में निर्वाचित करने का प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि इस मामले में उठाए गए बिंदुओं में से एक उन विशेष पंचों के बारे में है जिन्होंने इस आधार पर विवादित चुनावों में अवैध रूप से मतदान किया था कि वे निर्वाचित होने या पंचायत के पंच के रूप में बने रहने के योग्य नहीं थे। चूंकि वे पंचायत के किरायेदार थे। अधिनियम की धारा 13-ख निम्नानुसार है -

"इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत चुनाव याचिका के अलावा सरपंच या पंच के किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

निर्वाचन नियमावली का नियम 44 निम्नलिखित शब्दों में है -

"(1) अधिनियम की धारा 13-बी के तहत चुनाव याचिका को इलाका मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में सभा क्षेत्र स्थित है। वह इस संबंध में विहित प्राधिकारी होगा।

(2) याचिकाकर्ता याचिका के साथ प्रतिवादियों की संख्या के बराबर याचिका और उसके संलग्नकों की प्रतियां संलग्न करेगा।

(6) जब यह याचिका 1 फरवरी, 1972 को न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह और गोपाल सिंह के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आरएस मित्तल ने बिशन कौर बनाम *पंजाब राज्य और अन्य* आई.एल.आर. (1971) 1 पंजाब & हरियाणा 428 मामले में न्यायमूर्ति बीआर तुली के फैसले पर भरोसा किया और अभिवक्ता ने अपनी दलील के समर्थन में कहा कि प्रतिवादी नंबर 4 का सह-विकल्प "चुनाव" नहीं था, और इसलिए, अधिनियम की धारा 13-बी के तहत चुनाव याचिका में इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यह तर्क इस प्रस्ताव के समर्थन में दिया गया था कि धारा 13-बी, इसलिए, आक्षेपित सह-विकल्प के संबंध में इस याचिका को दायर करने पर रोक नहीं लगाती है। इसके बाद प्रतिवादियों को याचिका के प्रस्ताव की सूचना जारी करने का आदेश दिया गया। स्थगित प्रस्ताव की सुनवाई में, याचिका को स्वीकार कर लिया गया और पहली बार में एक खंडपीठ द्वारा सुनवाई करने का निर्देश दिया गया क्योंकि यह तर्क दिया गया है कि *बिशन कौर के मामले* में न्यायमूर्ति तुली का निर्णय लागू सह-विकल्प पर लागू नहीं होता है, और इसी तरह के बिंदुओं से जुड़ी याचिकाओं के संचय से बचने के लिए वांछनीय माना जाता था।

(7) इस संदर्भ में विचार किया जाने वाला पहला बिंदु यह है कि क्या नन्हती प्रतिवादी नंबर 4 को "चुनाव द्वारा" पंच के रूप में सह-चुना गया है या नहीं, और यदि हां, तो क्या पहले से चुने गए पंचों द्वारा पंच के रूप में उनके चुनाव को अधिनियम की धारा 13-बी के तहत चुनाव याचिका द्वारा प्रश्न में बुलाया जा सकता है या नहीं। यदि यह पाया जाता है कि अधिनियम और चुनाव नियमों के तहत चुनाव याचिका में सहयोजित पंच के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है, तो यह तय करना होगा कि *बिशन कौर के मामले* न्यायमूर्ति तुली के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है या नहीं।

(8) अधिनियम की धारा 13-ख और निर्वाचन नियमावली के नियम 44 को पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। ऊपर दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हमें दो बातों का पता लगाना होगा, अर्थात् (i) क्या सहयोजित पंच अधिनियम की धारा 3 (i) के अर्थ के भीतर "पंच" है या नहीं और (ii) क्या अधिनियम की धारा 5 और सह-विकल्प नियमों के तहत प्रतिवादी 4 को सह-चुना गया है, क्या यह धारा 13-ए (ई) के अर्थ के भीतर "चुनाव" का गठन करता है या नहीं। "पंच" को धारा 3 (i) में परिभाषित किया गया है, जिसका

अर्थ अन्य बातों के साथ-साथ ग्राम पंचायत का सदस्य "इस अधिनियम के तहत निर्वाचित या नियुक्त किया गया है और इसमें एक सरपंच शामिल है। यह स्पष्ट है कि एक सहयोजित महिला हमेशा उस अभिव्यक्ति की वैधानिक परिभाषा के अर्थ के भीतर एक "पंच" होगी, भले ही वह निर्वाचित हो या अन्यथा नियुक्त हो।

(9) ग्राम पंचायत का गठन मूल रूप से अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदान किया गया था। उक्त धारा (उपधारा 1 से 3) का संगत भाग जब मूल रूप से प्रधान अधिनियम में अधिनियमित किया गया था तो वह निम्नलिखित शब्दों में था -

(1) प्रत्येक सभा, विहित रीति से, अपने सदस्यों में से सभा का एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी समिति चुनेगी जिसमें कार्यकारी समिति के सरपंच सहित ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम से कम पाँच या नौ से अधिक नहीं होगी जैसा कि सरकार सभा क्षेत्र की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अवधारित करे:

परन्तु यदि कोई महिला किसी सभा की पंच के रूप में निर्वाचित नहीं होती है, तो उस चुनाव में महिला उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली महिला उम्मीदवार को पंचायत द्वारा उस सभा के पंच के रूप में सहयोजित किया जाएगा और जहां ऐसी कोई महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, विहित प्राधिकारी सभा की एक महिला सदस्य के रूप में ऐसे पंच के रूप में सह-चयन करेगा जो पंच के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो।

(2) अध्यक्ष को कार्यकारी समिति का सरपंच भी कहा जाएगा जिसे ग्राम पंचायत के रूप में स्टाइल किया जाएगा, उसके सदस्यों को पंच कहा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के परंतुक के अधीन पंच के रूप में सहयोजित प्रत्येक महिला को ग्राम पंचायत की बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा।

(4)\*\*\*\*\*

(5)\*\*\*\*\*

(10) इस स्तर पर यह देखा जा सकता है कि धारा 6 की उप-धारा (1) के परंतुक, जिसके तहत एक महिला को पंचायत में पंच के रूप में सह-चुना जाना था, मूल रूप से किसी भी आकस्मिकता में उस उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार के चुनाव का प्रावधान नहीं करता था। यदि एक या एक से अधिक महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था और उनमें से कम से कम एक पंच के रूप में चुनी गई थी, तो सह-विकल्प का कोई सवाल ही नहीं उठता था। यदि कोई भी महिला उम्मीदवार निर्वाचित नहीं होती है, तो पराजित महिला उम्मीदवारों में से सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले को पंचायत द्वारा सह-चुना जाना था। जहां ऐसी कोई महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थी, वहां निर्धारित प्राधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह ग्राम सभा की किसी भी महिला सदस्य को सह-चयन करे, जो पंचायत में ऐसे पंच के रूप में चुने जाने के योग्य हो सकती है। जब न्यायमूर्ति तुली ने *बिशन कौर के मामले* में कहा कि एक महिला पंच का सह-विकल्प "चुनाव" के बराबर नहीं है, जिसे चुनाव याचिका द्वारा रद्द करने की आवश्यकता होती है, तो विद्वान न्यायाधीश पंजाब के एक मामले से निपट रहे थे जो ऊपर उद्धृत मूल प्रावधान के तहत उत्पन्न हुआ था। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 6 के असंशोधित प्रासंगिक भाग के तहत कानूनी स्थिति के बारे में विद्वान न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अपवाद नहीं है। अधिनियम की धारा 6 में पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) अधिनियम (1971 का 13) की धारा 4 के संचालन द्वारा संशोधन किया गया। हरियाणा प्रथम संशोधन अधिनियम की धारा 4 ने नए प्रावधानों द्वारा प्रमुख अधिनियम की धारा 5 और 6 को बदल दिया। मूल धारा 6 के संगत भाग को धारा 5 की उप-धाराओं (2) और (3), नई अधिनियमित धारा 5 की उप-धाराओं (1), (2) और (3) में निम्नानुसार लाया गया है: -

(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक सलभा क्षेत्र में नाम से एक ग्राम पंचायत स्थापित कर सकती है।

(2) ऐसी प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या कम से कम पाँच या नौ से अधिक नहीं होगी जो सरकार सभा क्षेत्र की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अवधारित करे और ऐसे पंचों का निर्वाचन सभा द्वारा अपने सदस्यों में से विहित रीति से किया जाएगा:

परन्तु यदि किसी महिला को किसी ग्राम पंचायत के पंच के रूप में निर्वाचित नहीं किया जाता है, तो उस चुनाव में महिला उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली महिला उम्मीदवार को ग्राम पंचायत द्वारा उस ग्राम पंचायत के पंच के रूप में सहयोजित किया जाएगा और जहां ऐसी कोई महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, विहित प्राधिकारी सभा की एक महिला सदस्य के रूप में ऐसे पंच के रूप में सह-चयन करेगा जो पंच के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो।

(3) उपधारा (2) के परंतुक के अधीन पंच के रूप में सहयोजित प्रत्येक महिला को ग्राम पंचायत की बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा।

नए प्रावधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं है जो हमारे उद्देश्यों के लिए सामग्री हो। पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम (1971 का 29) की धारा 2 द्वारा प्रधान अधिनियम में प्रतिस्थापित प्रावधान की उप-धारा (2) के परंतुक में निम्नानुसार संशोधन किया गया था -

"बशर्ते कि यदि कोई महिला किसी ग्राम पंचायत के पंच के रूप में निर्वाचित नहीं होती है, तो निर्वाचित पंच, निर्धारित तरीके से, सभा की एक महिला सदस्य के रूप में पंच के रूप में सह-चयन करेंगे, जो इस तरह से निर्वाचित होने के योग्य है।

उपर्युक्त संशोधन 1 जून, 1971 से द्वितीय संशोधन अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) के संचालन से लागू हुआ, अधिनियम की धारा 101 के तहत बनाए गए सह-विकल्प नियमों को 22 सितंबर, 1971 को हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किया गया था। सह-विकल्प नियमावली के नियम 5 में महिला पंच के सह-विकल्प की विधि निर्धारित की गई है और यह निम्नलिखित शर्तों में है -

(1) किसी महिला पंच के सह-विकल्प के लिए नियुक्त समय और स्थान पर पीठासीन अधिकारी उपस्थित पंचों से सभा की उन महिला सदस्यों, जो पंच के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हैं, के नाम सह-विकल्प के लिए उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने के लिए कहेगा और प्रस्तावक के नाम के साथ प्रत्येक उम्मीदवार

का नाम लिखेगा और उम्मीदवार के नाम के आगे प्रस्तावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। प्रस्तावित:

बशर्ते कि एक पंच सह-विकल्प के लिए एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्ताव नहीं करेगा।

(2) सभी नामों के प्रस्तावित हो जाने के बाद, पीठासीन अधिकारी पंचों को उम्मीदवारों के नाम पढ़कर सुनाएगा और पंच के रूप में सहयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित उम्मीदवारों की पात्रता के विरुद्ध पंच द्वारा उठाई गई आपत्तियों, यदि कोई हो, को सुनेगा। पीठासीन अधिकारी सभा क्षेत्र से संबंधित राज्य विधान सभा की निर्वाचक नामावली से भी स्वयं को संतुष्ट करेगा चाहे उम्मीदवारों के नामों का उसमें उल्लेख हो या नहीं। यदि उम्मीदवार अधिनियम की धारा 5 या 102 के तहत पंच के रूप में चुने जाने के लिए योग्य नहीं पाया जाता है या उसका नाम मतदाता सूची में मौजूद है, तो उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा और अस्वीकृति के कारणों को लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके बाद पीठासीन अधिकारी पंचों को उन उम्मीदवारों के नाम पढ़कर सुनाएंगे, जिन्हें जांच के बाद पंच के रूप में सह-चयन के लिए सही तरीके से प्रस्तावित किया गया है।

(3) पीठासीन अधिकारी को सभा क्षेत्र से संबंधित राज्य विधान सभा की निर्वाचक नामावली की एक प्रति प्रदान की जाएगी।

(4) यदि महिला उम्मीदवार का केवल एक नाम प्रस्तावित है, तो पीठासीन अधिकारी ऐसी महिला को सहयोजित घोषित करेगा। अन्यथा, वह पंचों से निम्नलिखित उप-नियमों में निर्धारित तरीके से गुप्त मतदान द्वारा एक महिला पंच के सह-विकल्प का फैसला करने का आह्वान करेगा।

(5) पीठासीन अधिकारी उस स्थान पर जहां बैठक आयोजित की जाती है, ऐसी यांत्रिक युक्तियों के साथ एक मतपेटी प्रदान करेगा कि उसमें मतपत्र डाला जा सके,

लेकिन बॉक्स खोले बिना उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। मतपेटी को वहां रखा जाएगा जहां यह पीठासीन अधिकारी और पंचों को दिखाई दे।

(6) मतदान से तुरन्त पूर्व पीठासीन अधिकारी उपस्थित पंचों को खुली अवस्था में मतपेटी दिखाएगा, ताकि वे देख सकें कि पेटी खाली है। इसके बाद पंचों की उपस्थिति में मतपेटी को बंद और सील कर दिया जाएगा।

(7) (i) पीठासीन अधिकारी को फार्म क में पर्याप्त संख्या में मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे जिनमें मुद्रित चिह्न होंगे जिन पर चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों के नाम और विवरण प्रत्येक प्रतीक के विरुद्ध वर्णानुक्रम में हिन्दी में टाइप या स्पष्ट रूप से लिखे जाएंगे। पीठासीन अधिकारी उपस्थित सभी पंचों को मतपत्र का प्रदर्शन करके प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के आगे दिखाई देने वाले प्रतीक के बारे में पंचों को समझाएंगे।

(ii) मतदान करने के इच्छुक प्रत्येक पंच को एक मतपत्र प्रदान किया जाएगा। पंचों को सौंपे जाने से पहले मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। प्रत्येक पंच मतपत्र प्राप्त करने पर मतदान के लिए अलग किए गए स्थान पर जाएगा और फिर उस उम्मीदवार के नाम और प्रतीक के आगे लाल पेंसिल के साथ एक क्रॉस मार्क (एक्स) लगाएगा जिसके लिए वह मतदान करना चाहता है। इसके बाद वह मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डालेगा।

(8) यदि कोई पंच अंधा है या मतदान करने में शारीरिक रूप से अक्षम है, तो पीठासीन अधिकारी, उसके अनुरोध पर, उसे एक एजेंट के साथ जाने की अनुमति देगा, जो पंच की पसंद का पता लगाने के बाद, अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे एक्स मार्क लगाएगा और उसके बाद उसकी ओर से वोट डालेगा। एजेंट के उपयोग का एक नोट पीठासीन अधिकारी द्वारा रखा जाएगा जो नोट पर पंच और एजेंट दोनों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी प्राप्त करेगा।

(9) पीठासीन अधिकारी मतपत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा।

(10) मतदान समाप्त होने के बाद, पीठासीन अधिकारी पंचों की उपस्थिति में मतपेटियों को खोलेगा, यदि कोई हो, तो वोटों की गिनती करेगा और प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में अमान्य मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या को दर्शाते हुए एक विवरण तैयार करेगा, जिस पर पंच चाहें तो अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं।

(11) कोई मतपत्र जिस पर कोई निशान या हस्ताक्षर है जिसके द्वारा मतदाता की पहचान की जा सकती है जिस पर एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के आगे या अस्पष्ट तरीके से क्रॉस का निशान लगाया गया है या नहीं लगाया गया है या जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, अवैध घोषित किया जाएगा और पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर के तहत लाल पेंसिल में मतपत्र पर इसका रिकॉर्ड बनाएगा।

(12) पीठासीन अधिकारी उस उम्मीदवार को महिला पंच के रूप में घोषित करेगा जिसने सबसे अधिक वैध मत प्राप्त किए हैं:

बशर्ते कि यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों ने समान संख्या में वोट प्राप्त किए हैं, तो पीठासीन अधिकारी पंचों की उपस्थिति में ऐसे बहुत से उम्मीदवारों को आकर्षित करेगा और जिस उम्मीदवार का नाम पहली बार लिया गया है, उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा महिला पंच के रूप में सह-चयनित घोषित किया जाएगा।

(11) सह-विकल्प नियमावली की धारा 5 और नियम 5 की उपधारा (2) के परंतुक को पढ़ने मात्र से, जिसके उपबंधों के अंतर्गत दिसंबर, 1971 में विवादित चुनाव हुआ था, यह पता चलेगा कि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा किसी को सहयोजित महिला पंच के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रासंगिक समय पर कोई स्थान नहीं था और ऐसे पंच को किसी पात्र में से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुना जाना था। पूर्व में निर्वाचित पंचों द्वारा ग्राम सभा की योग्य महिला सदस्य। नियम 5 में निर्वाचन के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। धारा 13 ए (ई) में "चुनाव" शब्द को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "सरपंच या पंच के पद को भरने के लिए चुनाव। मैंने पहले ही ऊपर कहा है कि सह-विकल्प द्वारा पंच के पद को भरने के लिए नियुक्त एक महिला अधिनियम के अर्थ के भीतर एक "पंच" है। जब तक एक महिला सदस्य को सह-चुनने के लिए चुनाव

का कोई प्रावधान नहीं था (जैसा कि हरियाणा प्रथम संशोधन अधिनियम (1971 का 19) द्वारा हरियाणा में इसके संशोधन के बाद प्रमुख अधिनियम में और अधिनियम में भी), जिस प्रक्रिया के द्वारा एक महिला को पंचायत में सह-चुना गया था, उसे चुनाव नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वास्तव में वह निर्वाचित नहीं थी, लेकिन नियुक्त किया गया। सह-विकल्प नियमों के नियम 5 में अब एक महिला पंच के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बहुत विस्तार से बताया गया है। हरियाणा द्वितीय संशोधन अधिनियम (1971 का 29) द्वारा अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परंतुक में लाए गए परिवर्तन और सह-विकल्प नियमों के प्रख्यापन और प्रवर्तन के मद्देनजर, अब यह नहीं कहा जा सकता है कि महिला पंच का पद चुनाव से नहीं भरा जाता है। वास्तव में इसे अब चुनाव के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं भरा जा सकता है। बिशन कौर के मामले में न्यायमूर्ति तुली की टिप्पणियों को इस संबंध में ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि "सह-विकल्प एक छोटे निकाय द्वारा चुनाव का एक रूप हो सकता है, लेकिन इस अधिनियम के मामले में, अधिनियम की धारा 6 के तहत एक महिला पंच का सह-विकल्प 'चुनाव' के बराबर नहीं है, जिसे चुनाव याचिका द्वारा रद्द किया जा सकता है। न्यायमूर्ति तुली द्वारा इसे सही ढंग से आयोजित किया गया था क्योंकि हरियाणा संशोधन से पहले धारा 6 (1) के परंतुक के तहत चुनाव की कोई प्रक्रिया शामिल नहीं थी। विद्वान न्यायाधीश ने "सह-विकल्प" शब्द के शब्दकोश अर्थ पर ध्यान दिया - "अपने सदस्यों के वोटों से किसी भी निकाय में चुनाव करना", और फिर उपरोक्त उद्धृत टिप्पणियां कीं। मेरी राय में केवल "चुनाव" या "सह-विकल्प" शब्द का उपयोग करने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि पंच के चयन में चुनाव की प्रक्रिया शामिल है या नहीं। यहां तक कि अगर "चुनाव" शब्द का उपयोग प्रिंसिपल एक्ट की धारा 6 की उप-धारा (1) के परंतुक में किया गया था, तो उस प्रावधान के तहत नियुक्त महिला पंच को 'निर्वाचित' नहीं माना जा सकता था। जब तक एक महिला पंच को अब सह-विकल्प नियमों के नियम 5 द्वारा निर्धारित तरीके से केवल चुनाव द्वारा नियुक्त किया जाना आवश्यक है, तब तक केवल "सह-विकल्प" शब्द को बनाए रखने से इस तथ्य को दरकिनार नहीं किया जाएगा कि महिला सदस्य को भी एक अलग और छोटे निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ऐसा होने पर, उनके चुनाव को चुनाव याचिका के माध्यम से सवालियों के घेरे में बुलाया जा सकता है।

(12) हुइडा ने तर्क दिया है कि याचिका को तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पास चुनाव याचिका के माध्यम से एक वैकल्पिक सहारा था। उनके अनुसार, याचिकाकर्ता नंबर 1 इस वैकल्पिक उपाय के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 5 का चुनाव लड़ सकता था, और याचिकाकर्ता नंबर 2 प्रतिवादी नंबर 4 के चुनाव को चुनौती दे सकता था। इसलिए, वह सुझाव देते हैं कि याचिकाकर्ताओं को एक रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय से राहत मांगने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब वे चुनाव याचिका में अपने दावों को आगे बढ़ा सकते थे। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ के फैसले का हवाला दिया है, विशेष रूप से सुखदेव नारायण और अन्य बनाम महादेवानंद गिरि ए.आई.आर. 1961 पटना 475. का मामला। उस मामले में फैसले ने स्थापित किया कि अदालत के पास आवेदक के व्यवहार और इरादों की जांच करने का अधिकार है। इसके अलावा, अदालत अधिकार-पृच्छआदेश को रोकने का विवेक रखती है, खासकर उन स्थितियों में जहां एक वैकल्पिक उपाय मौजूद है जो उतना ही उपयुक्त और प्रभावोत्पादक है। इसके अलावा, इस बात पर जोर दिया गया कि जब वैधानिक प्रावधान चुनाव के संचालन को नियंत्रित करते हैं, तो अधिकार-पृच्छकी रिट लागू नहीं होती है। ऐसे मामलों में, कानून में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार चुनाव लड़ा जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय ने, सुखदेव नारायण (3) के मामले में रिट याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि चुनाव के समय उम्मीदवार की योग्यता की कमी के आधार पर चुनाव को अमान्य करने के लिए यथास्थिति उपाय की मांग करने के बावजूद, उम्मीदवार बाद में याचिका की सुनवाई के समय तक योग्य हो गया था, जिससे संभावित पुनर्निर्वाचन की अनुमति मिली। यह दृढ़ता से स्थापित है कि एक वैकल्पिक उपाय की उपस्थिति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत देने को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करती है। हालांकि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनावों के संदर्भ में, अनुच्छेद 329 (बी) एक पूर्ण प्रतिबंध बनाता है, जो उचित विधायी अधिनियम के अनुसार निर्धारित तरीके से नामित प्राधिकारी को प्रस्तुत एक चुनाव याचिका के माध्यम से छोड़कर चुनाव को किसी भी चुनौती को रोकता है। अधिनियम की धारा 13-बी एक समान सीमा स्थापित करती है, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि एक चुनाव को अधिनियम के अध्याय 2-ए के प्रावधानों के अनुसार केवल एक चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। जबकि यह सीमा अन्य न्यायालयों में चुनौतियों को रोकती

है, यह अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में बाधा नहीं डालती है। फिर भी, यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय आम तौर पर चुनाव याचिकाओं की सुनवाई के लिए अधिनियम के तहत नामित प्राधिकारी की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अनिच्छुक होगा।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आरएस मित्तल ने हमें उदे सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1972 पी.एल.जे.20 मामले में न्यायमूर्ति एडी कोशल के फैसले का हवाला दिया/ ने इस आशय के अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका को उसके किसी भी प्रावधान द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है यदि यह ग्राम पंचायत के चुनाव से संबंधित प्रश्नों से संबंधित है। यद्यपि उस मामले में यह माना गया था कि उच्च न्यायालय आम तौर पर ऐसी याचिका पर विचार करने से इनकार कर देगा जब चुनाव याचिका के वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया गया है, विद्वान न्यायाधीश द्वारा आगे कहा गया था कि रिट याचिका को इसकी अंतिम सुनवाई के चरण में खारिज करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के कारण यह सुनवाई योग्य नहीं है जब ऐसा नहीं हुआ है। केवल गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया और सुना गया, लेकिन विचाराधीन वैकल्पिक उपाय समय के साथ स्वयं ही प्रतिबंधित हो गया है। यह वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने विवेकाधिकार के प्रयोग के मामले में न्यायालय के लिए एक और वैध विचार हो सकता है, हालांकि हम इसे सभी मामलों पर लागू कानून के सामान्य सिद्धांत के रूप में निर्धारित करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। तथ्य यह है कि वर्तमान मामले में न केवल चुनाव याचिका दायर करने की सीमा की अवधि समाप्त हो गई है, बल्कि रिट याचिका दायर किए जाने के समय प्रतिवादी नंबर 4 के सह-विकल्प के खिलाफ चुनाव याचिका की विचारणीयता के बारे में वास्तविक संदेह था। उस संदेह का उल्लेख प्रस्ताव पीठ के आदेशों में भी किया गया है जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है। इस मामले की इन विशिष्ट परिस्थितियों में हमें इस आधार पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करने के बाद रिट याचिका को इस अंतिम चरण में खारिज करना अनुचित प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता हमारे द्वारा निर्धारित कानून के

अनुसार उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का उपयोग किए बिना इस न्यायालय में आए हैं। इसलिए, हम श्री हुड्डा की दूसरी आपत्ति को भी स्वीकार करने में उचित नहीं लगते।

(13) हम अधिकार-पृच्छकी प्रकृति में रिट जारी करने के दायरे से संबंधित कतिपय मामलों से निपटने के लिए बुलाए जाने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि इस तरह की रिट जारी करने के लिए शर्तों के बारे में शायद ही कोई विवाद है क्योंकि इन्हें मैसूर विश्वविद्यालय बनाम *सी.डी. गोविंदा राव और एक अन्य* A.I.R. 1965 S.C. 491-में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा आधिकारिक रूप से निर्धारित किया गया है। उस मामले में यह माना गया है कि इससे पहले कि कोई नागरिक अधिकार-पृच्छ की रिट का दावा कर सके, उसे अदालत को संतुष्ट करना होगा कि विचाराधीन कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है और कानूनी अधिकार के बिना एक हड़पने वाले द्वारा आयोजित किया जाता है, जो आवश्यक रूप से जांच की ओर जाता है कि क्या उक्त कथित हड़पने वाले की नियुक्ति कानून के अनुसार की गई है या नहीं।

(14) यह मुझे विवाद के गुण-दोष की ओर ले जाता है। पहला बिंदु जिस पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आरएस मित्तल द्वारा दोनों चुनावों (सह-चयनित पंच और सरपंच के) को लागू किया गया है, वह यह है कि विचाराधीन दो बैठकों की पूरी कार्यवाही अवैध थी और उसमें आयोजित चुनावों का परिणाम 17 दिसंबर की बैठकों के नोटिस के रूप में शून्य और अमान्य था। याचिकाकर्ता नंबर 1 पर 1971 में दी गई अवधि संबंधित नियमों द्वारा निर्धारित अवधि से कम थी। तथ्य यह है कि दोनों उद्देश्यों के लिए बैठकें मूल रूप से 13 दिसंबर, 1971 को बुलाई गई थीं, लेकिन कोरम के अभाव में उस दिन आयोजित नहीं की जा सकीं, और यह कि 17 दिसंबर, 1971 को आयोजित प्रत्येक बैठक एक स्थगित बैठक थी, और यह कि केवल तीन दिन का नोटिस था, न कि सात दिनों का नोटिस, इसलिए, विचाराधीन बैठकों के संबंध में अपेक्षित हमारे समक्ष विवादित नहीं है।

(15) प्रमुख निर्वाचन नियम, जिन्हें 9 जून, 1971 को अधिसूचित किया गया था, को 22 सितम्बर, 1971 के आधिकारिक हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हरियाणा ग्राम पंचायत (प्रथम संशोधन) निर्वाचन नियम, 1971 द्वारा हरियाणा राज्य में

उनके आवेदन में संशोधित किया गया है। संशोधित नियम 38(2) में प्रावधान है कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सभी पंचों को लिखित में एक नोटिस जारी करेंगे जिसमें सरपंच के चुनाव के लिए पंचों की बैठक की तारीख, समय और स्थान की जानकारी दी जाएगी। नियम 38 के उप-नियम (3) में इस प्रकार कहा गया है:-

“नोटिस प्रत्येक पंच के निवास के सामान्य स्थान पर बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले डाक द्वारा भेजा जाएगा और ब्लॉक के एक अधिकारी के माध्यम से भी दिया जाएगा और इसकी एक प्रति पंचायत के नोटिस-बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

परन्तु उपनियम (2) के अधीन नोटिस जारी होने के बाद निर्वाचित, सहयोजित या नामित पंच को पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से नोटिस जारी और दिया जाएगा जो वह बैठक से पहले उचित समझे।

यथा संशोधित नियम 39 के उप-नियम (1) में प्रावधान है कि पंचों की कुल संख्या के कम से कम आधे सरपंच के चुनाव के लिए कोरम का गठन करेंगे। उप-नियम (2) पीठासीन अधिकारी को कोरम की कमी के कारण सरपंच के चुनाव के लिए पहली बैठक स्थगित करने के लिए अधिकृत करता है। उपनियम (3) में कहा गया है -

"जब उप-नियम (2) के तहत एक बैठक स्थगित की जाती है, तो खंड विकास और पंचायत अधिकारी द्वारा नियम 38 के उप-नियम (2) और (3) में निर्धारित तरीके से पंचों को तीन दिन का स्पष्ट नोटिस देकर सरपंच का चुनाव करने के उद्देश्य से एक और बैठक बुलाई जाएगी। दूसरी बैठक के लिए कोई कोरम नहीं होगा।

नियम 38 और 39 के बाकी प्रावधान हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि जिस बैठक में धन सिंह प्रतिवादी को सरपंच के रूप में चुना गया था, वह चुनाव नियमों के नियम 39 के उप-नियम (3) के तहत आयोजित की गई थी, श्री मित्तल द्वारा यह तर्क दिया गया है कि बैठक केवल तभी वैध हो सकती है जब यह पहले याचिकाकर्ता सहित पंचों को "तीन दिन का स्पष्ट नोटिस" देकर आयोजित की गई हो। तर्क यह है कि 14 दिसंबर, 1971 को दिए गए नोटिस और 17 दिसंबर, 1971 को हुई बैठक में, तीन स्पष्ट दिनों में दोनों तारीखों के बीच हस्तक्षेप नहीं किया गया था,

लेकिन केवल दो स्पष्ट दिन, यानी 15 वीं और 16 वीं ने दोनों टर्मिनी के बीच हस्तक्षेप किया था। सह-विकल्प नियमों के नियम 3 और 4 चुनाव नियमों के नियम 38 और 39 की लगभग शब्दशः प्रतियां हैं। सह-विकल्प नियमावली के नियम 4 के उप-नियम (3) का वाक्यांश विज्ञान सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए संशोधित निर्वाचन नियमों के नियम 39 के उप-नियम (3) के रूप में नोटिस की अवधि के दृष्टिकोण से समान है। विचाराधीन दो बैठकों में से प्रत्येक के मामले में, निर्वाचित पंचों को "तीन दिन का स्पष्ट नोटिस" देना आवश्यक था। इस दृष्टिकोण से बैठकों की वैधता पर उच्चारण करने के लिए, हमें तीन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बुलाया जाता है, अर्थात्:-

- (i) क्या तीन दिन का नोटिस भेजने या देने में नोटिस जारी किए जाने की तारीख से तीन दिनों की गणना की परिकल्पना की गई है;
- (ii) क्या "तीन दिन का स्पष्ट नोटिस" वाक्यांश "तीन स्पष्ट दिनों की सूचना" का पर्याय है; और
- (iii) क्या "तीन दिन की स्पष्ट सूचना" की आवश्यकता अनिवार्य है या इस अर्थ में निर्देशिका है कि उस आवश्यकता का अनुपालन न करने से चुनाव में अनिवार्य रूप से गड़बड़ी होनी चाहिए या नहीं।

(16) नियमों की योजना पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मुझे सह-विकल्प नियमों के नियम 3 के उप-नियम (3) में "नोटिस डाक द्वारा भेजा जाएगा" और संशोधित चुनाव नियमों के नियम 38 के उप-नियम (3) में "भेजा गया" शब्द के उपयोग में बहुत महत्व दिखता है। इसी तरह, संशोधित चुनाव नियमों के नियम 39 के उप-नियम (3) के पहले भाग में "सेवा" शब्द का हटाना और सह-विकल्प नियमों के नियम 3 के उप-नियम (3) के शुरुआती भाग में उसी शब्द को हटाना ऐसे उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य वाक्यांशविज्ञान से जानबूझकर अलग होना दर्शाता है। नोटिस के संबंध में दोनों नियमों के संबंधित भाग के उप-नियम (3) में "सेवा" शब्द के बजाय "देना" शब्द का उपयोग किया गया है। एक तीसरा कारक जो इस संबंध में महत्वपूर्ण है, वह यह है कि "सेवा" शब्द का उपयोग नियम 38 के उप-नियम (3) के साथ-साथ नियम 3 (चुनाव नियम और सह-विकल्प नियम) के उप-नियम (3) में ब्लॉक के किसी अधिकारी के

माध्यम से या ग्राम सचिव के माध्यम से दिए जाने वाले नोटिस के संबंध में किया गया है। लेकिन डाक द्वारा नोटिस भेजे जाने और बैठक की तारीख के बीच समाप्त होने वाले दिनों की संख्या के विपरीत इस तरह के नोटिस की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों संबंधित नियमों के उप-नियम (3) में उल्लिखित तीन दिनों की अवधि का संबंध नोटिस देने से है, जो बदले में नोटिस भेजने से संबंधित है, न कि संबंधित पंचों को नोटिस के वास्तविक वितरण के समय से। जब उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (1916 का 2) की धारा 87-ए (3) में "सेवा" शब्द के स्थान पर "सेंड" शब्द के उपयोग के प्रभाव का सवाल जय चरण लाल अनल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ए.आई.आर. 1968 एस.सी.5 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया तो न्यायमूर्ति द्वारा यह माना गया था कि "भेजे" शब्द से पता चलता है कि महत्वपूर्ण तिथि नोटिस भेजने की तारीख है। उस मामले के तथ्यों पर उनके लॉर्डशिप ने पाया कि 25 तारीख को बुलाई गई बैठक के लिए 17 तारीख को "भेजा गया" नोटिस वैध था क्योंकि 17 और 25 तारीख के बीच सात स्पष्ट दिनों ने हस्तक्षेप किया था, और इसलिए, संबंधित प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। इसी प्रकार, एस. रमैया बनाम मैसूर राज्य और अन्य 1969 (1) एम.एल.जे.395 के मामले में मैसूर उच्च न्यायालय ने मैसूर नगरपालिका (राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति) चुनाव नियम, 1965 के उस नियम 9 (1) में यह अभिनिर्धारित किया कि बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम पाँच दिन पहले पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए, जो केवल सूचना भेजने से संबंधित है और सदस्यों से बैठक से पाँच दिन पहले सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं करता है। एक प्रासंगिक उदाहरण, रिटेल डेयरी कंपनी, लिमिटेड बनाम क्लार्क (1912) 2 के.बी.डी.388 को भी इस व्याख्या का समर्थन करने के लिए उद्धृत किया गया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि प्रावधान में किसी भी संकेत के अभाव में कि "भेजा गया" शब्द "प्रेषित" के सामान्य अर्थ के अलावा एक अर्थ रखता है, इसे तदनुसार समझा जाना चाहिए। चूंकि यह निर्विवाद है कि नोटिस 13 तारीख को भेजे गए थे और प्रथम याचिकाकर्ता द्वारा 14 दिसम्बर, 1971 को प्राप्त किए गए थे, इसलिए न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुसंगत नियमों की अपेक्षाएं पूरी की गई थीं, भले ही शर्त तीन स्पष्ट दिनों के लिए हो, क्योंकि समय की गिनती प्रेषण और नोटिस प्रावधान की तारीख से

शुरू होती है। इस बिंदु से उत्पन्न होने वाले दूसरे प्रश्न के संबंध में, अदालत ने उत्तरदाताओं के वकील से असहमति जताते हुए कहा कि संबंधित उप-नियमों में "स्पष्ट" शब्द का अर्थ दिनों की संख्या को योग्य बनाना है, न कि नोटिस की सामग्री को। उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क-कि अधिसूचनाओं में स्पष्टता, जैसा कि उपनियम (3) द्वारा आवश्यक है, सह-विकल्प नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) और संशोधित चुनाव नियमों के नियम 38 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट सभी आवश्यक विवरण प्रदान करना शामिल है-उप-नियम में "स्पष्ट" शब्द का उपयोग करने के उद्देश्य से असंगत माना गया था। (3). न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उपनियम (3) स्वतंत्र रूप से पूर्ववर्ती नियम के उपनियम (2) के अनुपालन को अनिवार्य करता है। नतीजतन, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पहले याचिकाकर्ता को दी गई दो बैठकों में से प्रत्येक के लिए नोटिस वैध था।

(17) बैठक नोटिसों की वैधता पर हमारे रुख को ध्यान में रखते हुए, श्री बीएस गुप्ता, राज्य के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत मामलों को संबोधित करना अनावश्यक है। इन मामलों को इस तर्क का समर्थन करने के लिए उद्धृत किया गया था कि जबकि प्रासंगिक नियमों में नोटिस भेजने या प्रदान करने का दायित्व अनिवार्य है, तीन दिनों या तीन स्पष्ट दिनों के लिए शर्त को अनुमत माना जाता है और बाद की आवश्यकता का पालन न करने से चुनाव अमान्य नहीं होगा:

- (i) *पायनियर लिमिटेड, लखनऊ बनाम लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य* 1964 आई एल.एल.जे.370

(ii) *उमानंद राय बनाम मुआवजा अधिकारी, धुबरी और अन्य* ए.आई.आर. 1966 असम और नागालैंड 81

(iii) *प्रताप सिंह बनाम श्री कृष्ण गुप्ता और अन्य* ए.आई.आर. 1956 एस.सी.140 और

(iv) *जय भगवान शर्मा और एक अन्य माटू राम और अन्य* 1963 पी.एल.आर.

न ही यह आवश्यक है कि पायनियर मोटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम नगर परिषद, नागरकोइल ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 684 और विभिन्न अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा पर श्री मित्तल द्वारा "स्पष्ट दिनों" की अभिव्यक्ति के अर्थ पर भरोसा किया गया था।

"स्पष्ट दिनों" के शब्द के विवेचन की आवश्यकता नहीं है, जिस पर श्री आर एस मित्तल ने पायनियर मोटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम म्युनिसिपल कौंसिल, नागरकोइल और कई अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ किया।

(18) श्री आर.एस.मित्तल ने आगे आधे-अधूरे तरीके से तर्क दिया कि प्रतिवादी 6 और 7 द्वारा डाले गए वोटों के कारण दोनों चुनाव प्रभावित हुए थे क्योंकि वे पंच के रूप में चुने जाने से अयोग्य होने के कारण मतदान करने के हकदार नहीं थे क्योंकि वे पहचैयत के किरायेदार थे। प्रतिवादी संख्या 6 और 7 के वकील ने कहा है कि यह आपत्ति बैठक के पीठासीन अधिकारी के समक्ष नहीं उठाई गई थी। हमने विचाराधीन चुनावों का रिकॉर्ड मांगा। रिकॉर्ड वाले सीलबंद कवर हमारी उपस्थिति में खोले गए और हमने पाया कि महिला पंच के अनुरोध पर इस संबंध में लिखित में आपत्ति ली गई थी और पीठासीन अधिकारी द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि चुनाव याचिका में उनके चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता था। हम उस आदेश के सामने कानून की ऐसी किसी भी त्रुटि को स्पष्ट करने में असमर्थ हैं जिसके लिए हमें इसे रद्द करने की आवश्यकता होगी। हमारी यह भी राय है कि एक बार प्रतिवादी 6 और 7 को पंच के रूप में चुने जाने के बाद, उनके चुनाव को दो बैठकों के पीठासीन अधिकारी द्वारा केवल इसलिए नहीं माना जा सकता था क्योंकि उनके सामने इस आशय का आरोप लगाया गया था कि वे निर्वाचित होने के योग्य नहीं थे। मित्तल ने तब तर्क दिया कि भले ही प्रतिवादी 6 और 7 विधिवत चुने गए हों, अधिनियम की धारा 5 (5) (बी) (हरियाणा द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़े होने का हकदार नहीं होगा या पंच नहीं रहेगा यदि वह किरायेदार या पट्टेदार है और ग्राम पंचायत के तहत किरायेदारी या पट्टे पर है। और इसलिए, हमें यह कहना चाहिए कि विवादित बैठकों की तारीख पर प्रतिवादी 6 और 7 किसी भी मामले में पंच के रूप

में कार्य करना जारी रखने के लिए अयोग्य थे। हम एक से अधिक कारणों से इस विवाद में प्रवेश करने में असमर्थ हैं। सबसे पहले, इस आरोप को संबंधित प्रतिवादियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, और इसमें तथ्य का ऐसा विवादित प्रश्न शामिल है जिसे इन कार्यवाहियों में आसानी से तय नहीं किया जा सकता है। दूसरे, यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि प्रतिवादी 6 और 7 अपने चुनाव के बाद पंचायत के किरायेदार बन गए, बल्कि यह कि उन्हें निर्वाचित होने पर भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यदि ऐसा होता तो अधिनियम की धारा 13-बी के तहत चुनाव याचिका द्वारा उनके चुनाव पर सवाल उठाया जाता। ऐसा नहीं करने के बाद, याचिकाकर्ता अब इस अप्रत्यक्ष तरीके से अपने चुनाव पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। तीसरा, याचिकाकर्ताओं ने पंचायत से पंचायत के पट्टों के प्रासंगिक रिकॉर्ड को तलब करने की भी परवाह नहीं की है, जो निर्णायक रूप से दिखा सकता था कि पंचायत की कोई भूमि संबंधित समय में प्रतिवादी 6 और 7 के साथ पट्टे पर थी या नहीं। इसलिए, हम वर्तमान याचिका में इस आपत्ति पर विचार करने का अपना तरीका खोजने में असमर्थ हैं।

(19) श्री आर.एस. मित्तल का अंतिम निवेदन यह है कि सरपंच का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि महिला पंच, जिसने उसमें मतदान किया था, को चुनाव से केवल एक घंटे पहले सह-चुना गया था और इसलिए, बैठक की कोई लिखित सूचना नहीं थी। तर्क में कुछ तर्क हो सकता है, लेकिन इसमें कोई सार नहीं है। सबसे पहले, इस बिंदु को विशेष रूप से रिट याचिका में नहीं लिया गया है, इसलिए यह मानना सुरक्षित नहीं है कि सरपंच के चुनाव के लिए बैठक का कोई नोटिस उन्हें नहीं दिया गया था। दूसरे, यह तथ्य कि उन्होंने बैठक में भाग लिया और चुनाव में अपना वोट डाला, संदेह से परे दिखाता है कि उन्हें बैठक की सूचना थी। तीसरा, निर्वाचन नियमावली के नियम 38 के उप-नियम (3) का परंतुक उस पर नोटिस की पर्याप्तता और सेवा के तरीके का पूर्ण उत्तर है। उन्हें पंच के रूप में चुना गया था क्योंकि बैठक के नोटिस नियम 39 के उप-नियम (3) के तहत पहले ही जारी किए जा चुके थे। ऐसे पंच को नियम 38 (3) (पहले ही पहले से उद्धृत) के परंतुक द्वारा पीठासीन अधिकारी द्वारा "बैठक से पहले उचित तरीके से" दिया जाना आवश्यक है। यह स्पष्ट रूप से किया गया था। इसलिए हमें श्री मित्तल के इस तर्क को भी खारिज करने में कोई संकोच नहीं है।

(20) चूंकि याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों में से कोई भी उनकी योग्यता पर सफल नहीं हुआ है, इसलिए हमारे लिए श्री B.S. गुप्ता द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त प्रस्ताव में तल्लीन होना अनावश्यक है। वह सर्वोच्च न्यायालय के प्रताप सिंह के मामले (उपर्युक्त) के फैसले पर भरोसा करते हैं, जिसमें सुझाव दिया गया है कि निर्देशिका प्रावधानों का पालन न करने के कारण चुनावों को रद्द करने में तकनीकीताओं की ओर अदालत का झुकाव अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, आंकार सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1972 पी.एल.आर.378में न्यायमूर्ति महाजन और सोढी के निर्णय पर विस्तृत चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका प्रतिवादियों के वकील ने उल्लेख किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तर्क इस तर्क पर आधारित है कि भले ही बैठकों के नोटिसों को अमान्य माना गया हो, इस न्यायालय को चुनाव परिणाम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बैठक के नोटिसों को देने में कथित मामूली देरी के कारण कोई अन्याय नहीं हुआ है।

ऊपर बताए गए कारणों से, मैं निम्नलिखित निष्कर्षों की पुष्टि करता हूं:

(i) अधिनियम की धारा 6 (1) के संबंध में बिशन कौर (2) के मामले में न्यायमूर्ति तुली द्वारा व्यक्त किए गए कानूनी सिद्धांत, जैसा कि 1971 के संशोधन से पहले था, आपत्तिजनक नहीं हैं।

(ii) मूल अधिनियम की धारा 6 (1) के प्रावधान के तहत महिला पंच का सह-विकल्प, इसके संशोधन से पहले और सह-विकल्प नियमों के निर्माण से पहले, 'चुनाव' के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करता है और इसलिए, इसे चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है।

(iii) 1971 के हरियाणा द्वितीय संशोधन अधिनियम (1971 का अधिनियम, 29) द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन महिला पंच का सह-विकल्प अधिनियम की धारा 13 (क) (ड) में यथा परिभाषित "निर्वाचन" का गठन करता है। चूंकि एक सह-चयनित महिला पंच को अधिनियम की धारा 3 (i) के तहत "पंच" माना जाता है, इसलिए उसके चुनाव को चुनाव नियमों के नियम 44 के साथ

अधिनियम की धारा 13-बी के तहत चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है।

(iv) जबकि अधिनियम की धारा 13-बी अधिनियम के तहत चुनाव पर सवाल उठाने के उपायों को विशेष रूप से एक चुनाव याचिका के लिए प्रतिबंधित करती है, यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करती है।

(v) यद्यपि उच्च न्यायालय आम तौर पर अधिनियम की निर्वाचन याचिका के दायरे में आने वाले चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से बचता है, संविधान उच्च न्यायालय को उन परिस्थितियों में अपने रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने से नहीं रोकता है जहां राहत से इनकार करने के परिणामस्वरूप प्रकट अन्याय हो सकता है और जहां चुनाव कार्यवाही के स्वीकृत रिकॉर्ड में कानून या अधिकार क्षेत्र की त्रुटि स्पष्ट है।

(vi) चुनाव नियमों के नियम 38 के उप-नियम (2) और (3) और सह-विकल्प नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) और (3) में निर्धारित अवधि, साथ ही चुनाव नियमों के नियम 39 (3) और सह-विकल्प नियमों के 4 (3) के तहत नोटिस के लिए तीन दिन की आवश्यकता, नोटिस भेजने या देने की तारीख से शुरू होती है, यानी, संबंधित पंच को इसकी डिलीवरी या सेवा के समय से नहीं।

(vii) चुनाव नियमों और सह-विकल्प नियमों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि 'तीन दिन का स्पष्ट नोटिस' शब्द का अर्थ 'तीन दिन का स्पष्ट नोटिस' के समान है, जिसका अर्थ है कि नोटिस भेजने की तारीख और बैठक की तारीख के बीच तीन दिन का अंतराल होना चाहिए।

(viii) निर्वाचन नियमों के नियम 39 के उपनियम (3) के साथ-साथ उपनियम (2) के उपबंध और नियम 38 के उपनियम (3) के दायरे का संबंध, किसी पंच को, जिसे निर्वाचित या सह-निर्वाचित किया गया हो, किसी पंच के निर्वाचन के लिए नोटिस जारी करने के पश्चात् दी गई सूचना से नहीं है। ऐसे पंच को नोटिस बैठक के पीठासीन

अधिकारी द्वारा चुनाव नियमों के नियम 38 (3) के प्रावधान के तहत उचित समझे जाने वाले तरीके से वैध रूप से दिया जा सकता है।

(21) पक्षकारों के वकील द्वारा हमारे समक्ष कोई अन्य तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया था। नतीजतन, यह याचिका विफल होनी चाहिए और लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।

न्यायमूर्ति आर.एन. मित्तल—में सहमत हूँ.

के.एस.के.

—

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा